कोलबियरिंग एरियाज (एक्वी.एण्ड डेवल्प.) एक्ट1957के तहत अधिग्रहित की गई भूमि वर्ष 1980के उपरांत किये गये कार्यो (भूमिगत,खनन) के वनसं0 अधि0 1980 के तहत संचालित शोभापुर खान के लिए **80.902 हे0** वन भूमि / राजस्व वन भूमि के लिये कार्योत्तर स्वीकृति बाबत **संक्षिप्त टिप्पणी**

संस्थान द्वारा कोल बियरिंग एक्ट 1957के तहत अधिग्रहित एवं शोभापुर खदान के भूमिगत खनन हेतु कुल 343.239 हे0 भूमि का उपयोग किया गया है। उपरोक्त भूमि मे से खदान मे कुल 273.259 हे0 वन भूमि का उपयोग किया गया। वनभूमि 273.259 हे0 मे से संस्थान द्वारा व0सं0अधि01980 के तहत (स्वीकृति क्रं0 8–130/91/एफसी दि0 03.02.1997 के तहत कुल 1349.248हे) स्वीकृति प्राप्त वनभूमि मे से **163.236 हे0** वनभूमि का उपयोग इस खदान हेतू किया गया। (273.259–163.236 = 110.023हे0) एवं व0सं0 अधि0 1980 के तहत (स्वीकृति क्रं0 8–95/2000/एफसी/792दिनांक 20.03.2001के तहत कुल 42.000हे0) स्वीकृति प्राप्त वनभूमि मे से **17.121 हे0** भूमि का उपयोग इस खदान के लिए खनन कार्य हेतू किया गया (110.023–17.121= **92.902हे0**)। इस प्रकार शेष वनभूमि 92.902हे0, कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत वर्ष 1980के पूर्व अधिग्रहित की गई है, **इसलिए 92.902 हे0 वनभूमि में से 12.000 हे0 वनभूमि मे खनन कार्य वर्ष 1980 के पूर्व सम्पादित हो जाने के कारण वन संरक्षण अधि0 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त नही की गई एवं आवश्यक भी नही थी,** (92.902–12.000 = **80.902हे0)।**

शेष वन भूमि 80.902 हे0 मे वर्ष 1980 के पश्चात खनन कार्य किये गये जिसका संस्थान द्वारा प्रस्ताव बनाकर व0सं0अधि01980 के तहत कार्योत्तर स्वीकृति हेतू वर्ष 2007 मे वन विभाग को प्रस्तुत किये गये।

आवेदित क्षेत्र 80.902 हे0 का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं0	अधिसूचना क्रं0 / दिनांक	प्रस्तावित वनभूमि (हे0में)	टिप्पणी
1	2760 / **19.09.1963**	39.617	वनभुमि का कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत अधिसूचना 1980 के पूर्व लेकिन खनन कार्य व.स.अधि. 1980 के पश्चात किया गया इस कारण यह प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतू प्रस्तुत किया गया है।
2	2617 / **21.08.1978**	41.285	
आवेदित क्षेत्र कुल		80.902	

भारत सरकार, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के **पत्र क्रं0** 43024/5/05/ **PRIW-1** दि.21.03.06 के तारतम्य में, पर्या0एवं वन मंत्रा0 के पत्र दि016.02.2006 (छायाप्रति संलग्न) के पत्रो का अवलोकन पश्चात विदित हुआ की व0सं0अधि01980के प्रभावी होने के पूर्व वनभूमि का को0बि0.एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहण किया गया हो तथा वर्ष,1980 पश्चात खनन कार्य करना हो तो ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि का व.सं.अधि.1980के तहत स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2006 मे, **AIG (Forest)** के पत्र से ज्ञात हुआ कि, व0सं0अधि0 1980 के प्रभावी होने के पूर्व वनभुमि का को0बि0एक्ट ,1957 के तहत अधिग्रहण किया गया हो तथा वर्ष 1980 के पश्चात भी खनन कार्य करना हो तो ऐसे वनभुमि पर व0सं0अधि01980प्रभावी रहेगा आवेदक संस्थान को संज्ञान मे आने के उपरांत क्षेत्र 80.902 हे0 का प्रस्ताव वन सं0अधि01980 के तहत कार्योत्तर स्वीकृति हेतू वन विभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया।

आवेदित क्षेत्र में खनन कार्य व0सं0अधि0 1980 के अस्पष्टता के कारण हुआ है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित करने का कष्ट करे।

भवदीय

क्षेत्रीय योजना अधिकारी

Area Planning officer
Pathakhera . Area . W.C.L

No. 43024 / 5 / 2005 / PRIW-I
Government of India
Ministry of Coal

New Delhi, dated the 21st March, 2006

To
Chairman-cum-Managing Director,
Central Coalfields Limited,
Dharbhanga House, Ranchi,
Jharkhand.

Subject : Points for seeking clarification on Forest land acquisition under CBA (A & D) Act,1957.

Sir,

I am directed to refer to CCL letter No. REV/ 05/ 510 dated 25th April, 2005 wherein clarifications on some of the issues on Forest land acquisition under CBA (A&D) Act, 1957 were sought. The matter has been examined in the Ministry in consultation with Ministry of Environment and Forests. A note containing the clarifications furnished by the Ministry of Environment and Forests is forwarded herewith.

Encls: As stated.

Yours faithfully,

(M. Shahabudeen)
Under Secretary

Ministry of Environment and Forests
(FC Section)

Note of Ministry of Coal at Page 1-2/NS may be referred.

In the note the opinion of Ministry of Environment and Forests has been sought on various issues. The point-wise opinion is given below :-

(a) Whether permission of Central Government is required for use of forest land acquired under CBA Act : If the land acquired under CBA Act involves forest land, provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 will be applicable. However, if such land has been acquired and broken before 25.10.1980 i.e. the date of enactment of FC Act, 1980, approval under FC Act will not be required. For the land acquired and /or broken after 25.10.1980 FC Act will be applicable. However, at the time of renewal of such leases, whether acquired before or after 25.10.1980, permission under FC Act will be required for continuation of mining.

(b) Payment of elements of compensation beyond provisions of CBA Act : While granting approval under Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land, various stipulations are made for mitigating the adverse affects of mining, like raising of Compensatory Afforestation (CA), Safety zone etc. The user agency is required to pay the cost of such measures imposed in lieu of the forest land diverted for non-forestry purpose under the Forest (Conservation) Act, 1980, like cost of CA, NPV, and Safety zone etc, or cost of any other condition imposed by the Central Government.

(c) GMK land recorded as "Jungle Jhari" and given Raiyati status : The Forest (Conservation) Act, 1980 is applicable to all types of forest land. The Supreme Court in its order dated 12.12.1996 has further clarified that that the word "forest" must be understood according to its dictionary meaning. This description covers all statutorily recognized forests, whether designated as reserved, protected or otherwise for the purpose of Section-2 (i) of the Forest (Conservation) Act, 1980. The term "Forest Land" occurring in Section-2 will not only include "Forest" as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record, irrespective of the ownership. The provisions enacted in the Forest (Conservation) Act, 1980 for the conservation of the forests and the matters connected therewith, must apply clearly to all forests so understood irrespective of the ownership or classification thereof. In view of the above, the provisions of FC Act will be applicable to land recorded as Jungle Jhari also.

(d) Penal action against Company's officials : If the forest land has been utilized in violation of any of the provisions of the Act, without the approval of the Central Government, the penal action lies against the guilty officials.

(Pankaj Asthana)
AIG (FC)
16.02.2006